Date 19.3.26

Publication: Mint

Coal India arm CMPDIL to float IPO on March 20

COAL CENTRAL MINE Planning and Design Institute (CMPDIL), an arm of state-owned Coal India, is gearing up to launch its initial public offering (IPO) on March 20. The public offering will conclude on March 24, while bidding for anchor investors will take place on March 18, according to the red herring prospectus (RHP).

Date 20.03.26

Publication: The Statesman

CIL taking adequate measures to ensure coal supply to all consumers: Government

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 19 March

Amid the ongoing West Asia conflict, the government on Thursday said Coal India Limited (CIL) is taking adequate measures to ensure supply of coal to all consumers including the small, medium and other consumers.

"As a proactive step, CIL has planned 29 e-auctions in the month of March 2026 offering about 23.56 MT of coal. Out of these 29 auctions, 5 auctions have already been conducted since 12th March, 2026, wherein 73.1 lakh ton of coal was offered and 31.96 lakh ton of coal has been booked, indicating adequacy of coal offered in the e-auctions," the Ministry of Coal said in a statement.

In addition to this, CIL has also taken necessary action to ensure coal availability to the small, medium and other consumers through the State Nominated Agencies (SNAs) route and requested the state governments to provide the additional coal requirement, which can be met in full to avoid any energy shortages.

The coal offtake of the states through the SNAs is being constantly monitored by CIL to ensure that uninterrupted supplies are ensured. According to the Ministry, coal is continuing to ensure reliable baseload power to support core industries such as steel and cement that underpin the economic growth of the country. The coal production in the country continues at a pace matching with the prevailing demands of the consumer and building adequate stocks at the mine-end for maintaining adequate supplies to the consumers as per their requirements with the continued support of Railways, the statement said.

The pithead coal stock at the mines of CIL, which was 106.78 MT as on 1 April 2025 has grown to about 125.54 MT as on 18 March 2026.

Further, there is around 5.75 MT of coal at the mines of Singareni Collieries Company Limited (SCCL) and another 15.75 MT coal at the mines of captive/commercial mines and about 12 MT in transit and about 5.49 MT in ports and good-shed sidings.

This coal stock is in addition to the coal already available at the power plants which is around 53.41 MT, adequate for nearly 23 days at the present rate of consumption.

"The Ministry of Coal remains steadfast in its commitment to fostering a stable, transparent, and performance-driven ecosystem through sustained policy facilitation, robust monitoring mechanisms, and proactive stakeholder engagement. These concerted efforts are aimed at ensuring reliable coal availability, enabling uninterrupted operations across critical sectors, and effectively meeting the nation's growing energy demands, thereby advancing the long-term national vision of a Viksit Bharat by 2047," the statement added.

Date 20.03.26

Publication: Business Standard (H)

कोयले की निर्बाध आपूर्ति के लिए उपाय कर रही कोल इंडिया

पश्चिम एशिया संकट के बीच सभी उपभोक्ताओं के लिए कोयले की आपूर्ति बनाए रखने के लिए 29 ई-नीलामी करने की योजना

साकेत कुमार
नई दिल्ली, 19 मार्च

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण देश भर में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सभी उपभोक्ताओं, खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के कदम उठाए हैं। सरकार बदलती मांग की परिस्थितियों के बीच ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने पर काम कर रही है।

इसी रणनीति के तहत कंपनी ने मार्च 2026 में 29 ई-नीलामी करने की योजना बनाई है जिसमें करीब 2.35 करोड़ टन कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। 12 मार्च के बाद हुई पांच नीलामियों में 73.1 लाख टन में से 31.96 लाख टन कोयला बुक हुआ जिससे बाजार में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता के संकेत मिलते हैं।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी पहले की रिपोर्ट में यह बताया था कि कैसे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के छोटे उपभोक्ता, जैसे कैटरिंग और रेस्तरां कारोबार से जुड़े लोग रसोई गैस (एलपीजी) की कमी के कारण कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन के साथ काम चला रहे हैं। अनौपचारिक बाजार में कोयले की कीमतों में करीब 50 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है।

देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा देने वाली सीआईएल, राज्य नामित एजेंसियों (एसएनए) के माध्यम से छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने राज्यों से अतिरिक्त जरूरतों की जानकारी देने को कहा है ताकि किसी संभावित कमी से बचा जा सके। साथ ही, राज्यों द्वारा कोयले की खपत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि बिना किसी बाधा के आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

यह आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब देश में कोयले का भंडार पर्याप्त है। 18 मार्च 2026 तक सीआईएल की खदानों में 12.55 करोड़ टन कोयला मौजूद था, जो 1 अप्रैल 2025 के 10.67 करोड़ टन से अधिक है। इसके अलावा, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के पास 57.5 लाख टन, घरेलू और वाणिज्यिक खदानों में 1.57 करोड़ टन, ट्रांजिट में 1.2 करोड़ टन और बंदरगाहों आदि पर 54 लाख टन कोयला उपलब्ध है। थर्मल ऊर्जा संयंत्रों में भी कोयले का भंडार मजबूत स्थिति में है। यहां 5.34 करोड़ टन कोयला मौजूद है, जो मौजूदा खपत के अनुसार लगभग 23 दिनों के लिए पर्याप्त है।

सरकार का कहना है कि कोयला उत्पादन मांग के अनुसार जारी है जिससे इस्पात और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों को स्थिर आपूर्ति मिल रही है, साथ ही देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार भी हो रहा है। कोयला मंत्रालय ने नीति समर्थन, निगरानी और सभी हितधारकों के सहयोग से स्थिर आपूर्ति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।